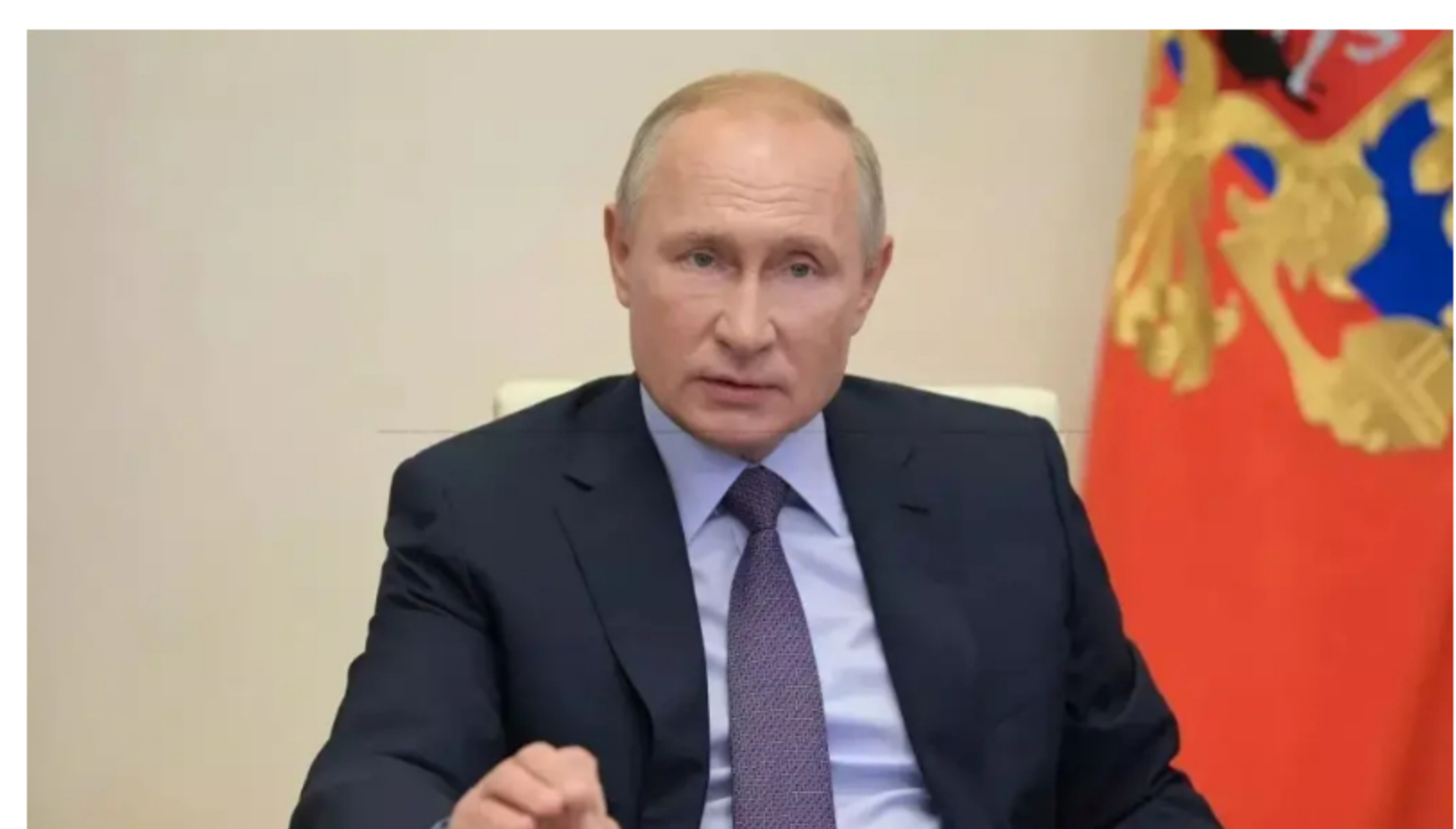




‘रूस हर हाल में यूक्रेन में अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा’, शांति प्रस्ताव से पहले बोले राष्ट्रपति पुतिन

नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस हर हाल में यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। यह लक्ष्य प्राप्ति कूटनीतिक रास्ते से होगी या फिर सैन्य शक्ति के इस्तेमाल से।

साथ ही वह रूस और यूक्रेन के मध्य सिव्युरिटी बफर जॉन को और ज्यादा चौड़ा करना चाहेंगे जिससे भविष्य में टकराव का खतरा पैदा न हो। पुतिन का यह बयान यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका का नया शांति प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले आया है।

रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा: पुतिन पुतिन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य कार्रवाई के लक्ष्यों को निसंदेह प्राप्त किया जाएगा। हम इन लक्ष्यों को कूटनीति के जरिये प्राप्त करना चाहते हैं। हम उन कारणों को

हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं जिनकी वजह से यह लड़ाई हो रही है।

अगर विरोधी पक्ष (यूक्रेन) और उसके विदेशी संरक्षक (पश्चिमी देश) मामले में वस्तुपरक वार्ता से इन्कार करते हैं तो रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य शक्ति से मुक्त कराएगा। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच चौड़ा बफर बनाया जाएगा जिससे टकराव के खतरे को टाला जा सके। विदित हो कि रूस के पास यूक्रेन का हिस्सा रहा पूरा क्रीमिया, डोनबास का 90 प्रतिशत भाग, खेरसान और जपोरीजिया के 75-75 प्रतिशत भाग कब्जे में आ चुके हैं। पुतिन ने अपने बयान में साफ किया है कि रूस की यूरोपीय देशों पर हमले की कोई योजना नहीं है, पश्चिमी देशों के नेता बेवजह युद्धोन्माद की स्थिति बना रहे हैं। (न्यूज एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

दिल्ली-NCR में प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

दिल्ली-NCR में प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश – स्कूल बंद, वर्क-फ्रॉम-होम और वाहनों पर सख्ती

नई दिल्ली | दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2025 को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई बड़े निर्देश जारी किए। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी और जिम्मेदार संस्थाओं को हर 15 दिन पर लगातार सुनवाई के लिए प्रस्तुत होना होगा। इस दौरान कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों को “आंशिक और असमर्थ” बताते हुए आलोचना भी की। सबसे अहम निर्देशों में दिल्ली में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के लिए स्कूलों को बंद करना शामिल है। अदालत ने यह निर्णय दिल्ली सरकार के प्रदूषण के कारण स्कूल बंद करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुना, लेकिन कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सरकारी आदेश के अनुसार इस समय जाड़े की छुट्टियाँ भी शुरू होने वाली हैं और बच्चों के स्वास्थ्य न सिर्फ स्कूल बंदी, 50% कर्मचारियों के



को ध्यान में रखते हुए यह कदम उचित माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वाहनों को मिलने वाली छूट में भी संशोधन किया और आदेश दिया कि अब केवल BS-IV या उससे ऊपर के वाहन ही छूट के पात्र होंगे, जबकि BS-III और उससे नीचे के वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। इससे वाहनों से निकलने वाले धुएँ को कम करने में मदद मिलेगी। न सिर्फ स्कूल बंदी, 50% कर्मचारियों के

लिए वर्क-फ्रॉम-होम (WFH) अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक और वाहनों की बढ़ती आवाजाही को रोककर प्रदूषण कम हो सके। यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण III-IV के अंतर्गत लिया गया है और आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। सड़क पर वाहनों के चलने पर भी पाबंदियाँ लागू की जा रही हैं, और दिल्ली सीमा पर टोल बूथों को

हटाने पर भी विचार करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया ताकि टोल बूथों पर लंबी गाड़ियों की कतारों से निकलने वाला धुआं कम हो।

निर्माण गतिविधियों के बंद होने से प्रभावित मजदूरों के लिए मुआवजे और वैकल्पिक रोजगार योजनाओं पर कार्य करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के कारण नौकरी खोने वाले मजदूरों को सुरक्षा मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण सिर्फ तात्कालिक आदेशों से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए दीर्घकालिक योजनाओं और सतत प्रयासों की आवश्यकता है जिससे भविष्य में ऐसे संकट को रोका जा सके।



आधार डाटा पूरी तरह सुरक्षित, अब तक कोई सैंधमारी नहीं: सरकार

नई दिल्ली — सरकार ने संसद को स्पष्ट किया है कि अब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डाटाबेस से आधार कार्ड धारकों की किसी भी जानकारी में कोई लीक या सैंधमारी नहीं हुई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि मजबूत तकनीकी और संस्थागत सुरक्षा उपायों के कारण आधार प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है।

उन्होंने कहा कि आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जिसके 134 करोड़ सक्रिय धारक हैं और अब तक इसमें 16 हजार करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण किए जा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार, डाटा की सुरक्षा के लिए मल्टी-लेयर सिव्योरिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया है, जिसमें उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीक और नियमित ऑडिट शामिल हैं। सरकार ने दोहराया कि आधार डाटा का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं हुआ है।

सिडनी हमले के बाद व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने ‘कट्टर इस्लामी आतंकवाद’ के खिलाफ एकता का आह्वान किया

वॉशिंगटन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस में हनुक्का (यहूदी त्योहार) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वैश्विक समुदाय से कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का जोरदार संदेश दिया। यह बयान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर आतंकवादी हमले के बाद आया, जिसमें यहूदी समुदाय के लोगों पर गोलियाँ चलीं और कई लोग मारे गए तथा घायल हुए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अनुसार यह हमला इस्लामिक स्टेट (ISIS) से प्रेरित था, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत और 25 से अधिक घायल हुए हैं।



ट्रंप ने कहा कि इस तरह की कट्टरपंथी हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को मिलकर लड़ना जरूरी है। उन्होंने सिडनी हमले के पीड़ितों के प्रति “प्रेम और प्रार्थना” भेजी और शोक व्यक्त किया, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद जताई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यह भी दोहराया कि

अमेरिका यहूदी समुदाय का हमेशा समर्थन करेगा और उन लोगों का मित्र बना रहेगा जो आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप के इस आह्वान का संदेश दुनिया भर के नेताओं और नागरिकों को एक साथ आतंकवादी ताकतों का सामना करने की आवश्यकता की ओर ध्यान खींचता है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद किसी एक देश तक सीमित खतरा नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर फैल चुका है, और इसे रोकने के लिए सभी देशों को साझा रणनीति अपनानी चाहिए।

सिडनी हमले के संदर्भ में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यहूदी समुदाय के साथ एकजुटता और समर्थन की प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिससे अमेरिकी नेतृत्व आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय लड़ाई में अपना पक्ष स्पष्ट कर रहा है। उनके इस संदेश का मकसद कट्टरता और हिंसा को अस्वीकार करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साथ खड़ा करना है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना वक्त की महत्वपूर्ण जरूरत बन गया है, खासकर तब जब सिडनी जैसे शहरों पर ऐसी हिंसक घटनाएँ हो रही हैं।

U19 एशिया कप 2025: भारत ने श्रीलंका से भिड़ेंगे सेमीफाइनल में,

फाइनल में भारत-पाकिस्तान की संभावित भिड़ंत



U19 एशिया कप 2025 के राउंड ऑफ़ 4 (Super 4) के बाद सेमीफाइनल में चार टीमों पक्की हो गई हैं। ‘अ’ ग्रुप में भारतीय अंडर-19 टीम ने तीनों मुकाबले जीतते हुए शानदार प्रदर्शन किया और पहले स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित की है। वहीं इसी ग्रुप में श्रीलंका ने भी दो जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस कारण भारत का पहला सेमीफाइनल श्रीलंका के विरुद्ध निर्धारित हुआ है। भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल मुकाबला 19 दिसंबर को दुबई के ICC अकादमी ग्राउंड पर सुबह 10:30 बजे (भारतीय समय) शुरू होगा।

दूसरी तरफ, ‘ब’ ग्रुप से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीमों ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इस समूह में बांग्लादेश ने तीन में से तीन मैच जीतकर शानदार फॉर्म दिखाई है, जबकि पाकिस्तान ने दो

जीत के साथ दूसरे स्थान पर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा सेमीफाइनल भी 19 दिसंबर को ही दुबई के The Sevens स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मुकाबला भी दर्शकों के लिए रोमांचक साबित होने की उम्मीद है।

इन दोनों सेमीफाइनलों के परिणाम के आधार पर फाइनल की संभावनाएँ तय होंगी। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतते हैं, तो 21 दिसंबर को आयोजित होने वाले फाइनल में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है — जो युवा क्रिकेट प्रशंसकों के लिए खास मैच होगा।

भारत की अंडर-19 टीम इस टूर्नामेंट में मजबूत रूप से खेल रही है और उनका लक्ष्य U19 एशिया कप का खिताब जीतना है। वहीं श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों भी अपनी-अपनी तैयारी और अनुभवों के साथ जीत की राह पर हैं। सेमीफाइनल मैचों से पहले पिच रिपोर्ट, टीम संयोजन और रणनीतियों पर सभी टीमों की नज़रें टिकी हुई हैं। इस टूर्नामेंट का फोकस युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमक दिखाने का अवसर देना है और 19 वर्ष से कम उम्र के क्रिकेटर्स की यह स्पर्धा आने वाले भविष्य के सितारों को पहचानने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होती है।



ग्रेच्युटी सीमा ₹20 लाख पर नागपुर हाईकोर्ट का अहम आदेश, राज्य सरकार को 8 सप्ताह में पुनः निर्णय के निर्देश

कुलकर्णी विजय शरदचंद्र व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (रिट याचिका क्रमांक 4969/2025) में न्यायमूर्ति अनिल एस. किलोर एवं न्यायमूर्ति रजनीश आर. व्यास की खंडपीठ ने 12 दिसंबर 2025 को यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी ₹20 लाख की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा का लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने 10.10.2024 के शासन निर्णय से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹14 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की है, लेकिन कुछ विभागों द्वारा पुराने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह लाभ देने से इनकार किया जा रहा है। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग (PWD), नागपुर क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा 28 जुलाई 2025 को जारी पत्र में याचिकाकर्ताओं को लाभ देने से मना किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ए.सी. धर्माधिकारी ने दलील दी कि यह मुद्दा पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Association of College and University Superannuated Teachers बनाम भारत संघ (सिविल अपील क्रमांक 908/2013, निर्णय दिनांक 30.01.2013) में तय किया जा चुका है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर आदेश की अनदेखी की गई।

नागपुर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी) की अधिकतम सीमा ₹20 लाख किए जाने संबंधी शासन निर्णय (GR दिनांक 10 अक्टूबर 2024) को लेकर दायर याचिका पर नागपुर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादी क्रमांक-1 (राज्य शासन) को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रत्येक आधार पर विचार करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि 28.07.2025 के आदेश की भी उसी कसौटी पर पुनः जांच की जाए और हर बिंदु पर स्पष्ट कारणयुक्त निष्कर्ष दर्ज किया जाए। यदि दावा अस्वीकार किया जाता है, तो उसका ठोस कारण बताना अनिवार्य होगा।

न्यायालय ने यह निर्णय लेने के लिए 8 सप्ताह की समय-सीमा तय की है और निर्णय की सूचना याचिकाकर्ताओं को उसके दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया।

किसे मिलेगा लाभ:

इस फैसले से महाराष्ट्र के वे सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं जो 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें अब तक ₹20 लाख की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिला है। यदि राज्य सरकार पुनर्विचार में अनुकूल निर्णय लेती है, तो ऐसे सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया सहित लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s unchanged.

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026: राजनीति, तारीखें और रणनीति – एक संपादकीय विश्लेषण

संपादकीय... |

महाराष्ट्र 2026 के नगर निगम (Municipal Corporation) चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक तापमान आज (17 दिसंबर 2025) बेहद गर्म है। यह चुनाव न केवल राज्य के शहरी शासन को आकार देगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा और राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। इसी संदर्भ में नीचे सबसे विश्वसनीय समाचार एजेंसियों और रिपोर्टों के आधार पर विस्तारपूर्वक संपादकीय विश्लेषण प्रस्तुत है।

1. चुनाव का ऐलान: तारीखें और प्रक्रिया

राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने 29 नगर निगमों सहित मुंबई की Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) के लिए मतदान की तारीख 15 जनवरी 2026 घोषित कर दी है और गिनती 16 जनवरी 2026 को होगी।

इन निगमों में कुल 2,869 सीटें हैं और 3.48 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के लिए पात्र हैं — जिसमें मुंबई के 227 वार्ड के 1.03 करोड़ से ज़्यादा मतदाता शामिल हैं।

चुनाव प्रक्रिया इस प्रकार है: नामांकन 23-30 दिसंबर तक, स्कूटनी 31 दिसंबर, नाम वापस 2 जनवरी और प्रतीक आवंटन व अंतिम सूची 3 जनवरी को जारी होगी।

2. राजनीतिक समीकरण: गठबंधन और रणनीति

महा-युति की स्थिति

राज्य की शासन गठबंधन महा-युति (Mahayuti) — जिसमें भाजपा (BJP), एकनाथ शिंदे शिवसेना और उनके सहयोगी शामिल हैं — ने स्पष्ट किया है कि वह इन चुनावों में साथ लड़ने का निर्णय ले चुके हैं। यह निर्णय नागपुर में शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गठबंधन की मजबूती पर ज़ोर दिया।

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले (Bawankule) ने तो यहां तक कहा कि महायुति सभी 29 नगर निगमों में जीत का लक्ष्य रखती है।

मुख्य विपक्षी गठबंधन की स्थिति

दूसरी ओर, महाअभिक विकास आघाड़ी (MVA) — जिसमें शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), NCP-SP और कांग्रेस शामिल हैं — भी सक्रिय रणनीति बना रही है। खासकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे (MNS) के बीच गठबंधन की तैयारी हो रही है, जो मुंबई समेत छह प्रमुख नगर निगमों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी।

कांग्रेस ने भी अपने स्थानीय इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे महायुति से अलग किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं।

पवार गुटों में सक्रियता

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भी भिन्न समूह चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। शरद पवार गुट (NCP-SP) ने अजित पवार गुट को महा-युति को हराने हेतु साझेदारी का प्रस्ताव दिया है, जिससे राजनीतिक समीकरण और जटिल होते दिख रहे हैं।

3. मुख्य राजनीतिक संकेत

कठिन मुकाबला और संभावित टक्कर

विश्लेषक मानते हैं कि बीएमसी चुनाव में सीधा मुकाबला महा-युति और MVA के बीच होने की उम्मीद है, खासकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में।

बीएमसी जैसा निकाय सिर्फ सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि यह एशिया की सबसे अमीर नगर निगम भी है, जिसका बजट लगभग ₹74,000 करोड़ से अधिक है। इसलिए सत्ता पर नियंत्रण पा लेना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है।

4. दलों की तैयारियाँ और उम्मीदवार चयन

राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रियाएँ भी शुरू कर दी हैं। उदाहरण के लिए नाशिक नगर निगम के लिए BJP, शिवसेना, NCP, MNS और कांग्रेस सभी उम्मीदवारों की साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, जिसका असर स्थानीय समीकरणों पर देखा जाएगा।

इस चरण में उम्मीदवार की जीतने की क्षमता, संगठन की तैयारी, और स्थानीय मुद्दों के अनुसार चयन प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

5. चुनाव का राजनीतिक महत्व

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव महज़ स्थानीय शासन का मामला नहीं रह गए हैं। ये चुनाव राजनीतिक शक्ति संतुलन, स्थानीय स्तर पर सरकार की लोकप्रियता, और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दिशा तय करेंगे।

नगर निगमों का नियंत्रण सत्ता को शहरी नीति, संसाधन वितरण, नागरिक सेवाएँ, और सार्वजनिक छवि पर बड़ा प्रभाव देता है। इसलिए दोनों पक्ष इन चुनावों को रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक मान रहे हैं।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव 2026 न केवल तारीखों और प्रक्रिया का मामला हैं, बल्कि राजनीतिक रणनीति, गठबंधन रचना, और स्थानीय राजनीति की निर्णायक लड़ाई का प्रतीक हैं।

15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी को नतीजों के साथ यह चुनाव राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पुनः रेखांकित करेगा। वर्तमान में महा-युति, MVA तथा अलग-अलग गठबंधनों की तैयारियाँ चुनाव को बेहद प्रतिस्पर्धी बनाती हैं — और आने वाले हफ्तों में यह प्रतिस्पर्धा और तेज़ होने की पूरी संभावना है। बरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य की राजनीतिक दिशा बदलने वाला निर्णायक मोड़ भी मान रहे हैं, जिसका प्रभाव आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों तक दिखेगा।

Chabahar Port | **भारत के चाबहार बंदरगाह का मुरीद हुआ रूस**

Chabahar Port: भारत के चाबहार बंदरगाह का मुरीद हुआ रूस, नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में करेगा शामिल, ईरान की बल्ले-बल्ले

तेहरान | भारत संचालित ईरान के

चाबहार बंदरगाह पर रूस नजर गड़ाए बैठा है। रूस ने चाबहार को दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार बताया है, जो यूरोप और मध्य एशिया से दक्षिण और पूर्वी एशिया को कनेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ईरान के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में चाबहार बंदरगाह को शामिल करने का भी फैसला किया है। रूस के इस फैसले से ईरान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो इस कॉरिडोर में जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों से योगदान देगा। रूस की प्लानिंग इस कॉरिडोर से भारत से रूस के रास्ते यूरोप को कनेक्ट करने की है।

ईरान और रूस के बीच बड़ी बैठक

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और रूस के ट्रांसपोर्ट उप प्रधानमंत्री ने तेहरान में उच्च-स्तरीय बातचीत के दौरान रणनीतिक नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर (INSTC) के लागू होने की प्रक्रिया को तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।



अली लारीजानी ने मंगलवार को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय में विटाली सवेलीव से मुलाकात की और बातचीत की। यह बैठक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच उच्चतम स्तर पर हुए समझौतों के बाद हुई, जिसका मकसद मौजूदा बाधाओं को दूर करना और प्रोजेक्ट को उसके ऑपरेशनल चरण में ले जाना था।

नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर पर चर्चा रिपोर्ट में बताया गया कि बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आकार देने वाले एक प्रमुख

भू-राजनीतिक घटक के रूप में समीक्षा की। नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) जहाज, रेल और सड़क मार्गों का एक नेटवर्क है जो सात हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और उत्तरी यूरोप को दक्षिणी एशिया से जोड़ता है। लारीजानी ने कहा कि ईरान ने कॉरिडोर को चालू करने का पक्का फैसला किया है, और वादा किया कि सभी कार्यकारी और संस्थागत बाधाओं को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के कानूनी और ऑपरेशनल ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

**इमरान खान और असीम मुनीर में हो सकती है दोस्ती?



इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान लंबे समय से अदियाला जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें देशद्रोह, भ्रष्टाचार और खुफिया जानकारी लीक करने का मामला भी शामिल है। इमरान खान के जेल जाने का प्रमुख कारण उनकी पाकिस्तानी सेना के साथ मतभेद भी है।

ये मतभेद जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल में शुरू हुए और सीडीएफ असीम मुनीर के कार्यकाल तक जारी हैं। हालांकि अब ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के बीच सुलह हो सकती है।

सेना से बात कर रहे PTI नेता द न्यूज की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान तहरी-ए-इंसाफ (PTI) के पूर्व नेताओं, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक समूह ने देश में राजनीतिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से, खासकर सेना और PTI के बीच, एक सुलह की पहल को चुपचाप आगे बढ़ाया है। यह पहल राष्ट्रीय संवाद बातचीत का समर्थन किया है और इसे समिति के बैनर तले की जा रही है, जिसमें सूत्रों के अनुसार, कई तरीका बताया है। हालांकि, इमरान खान ने पहले उनकी सलाह को खारिज

शामिल हैं। कहा जाता है कि यह तिकड़ी PTI के लिए राहत पाने और बातचीत के लिए जगह बनाने की कोशिश में एक "अधिकारी" के साथ-साथ सरकारी मंत्रियों के संपर्क में है।

कोट लखपत जेल पर सबकी नजर PTI संस्थापक इमरान खान की अदियाला जेल में कैद पर केंद्रित पहले के प्रयासों के विपरीत, समूह का तत्काल ध्यान कोट लखपत जेल पर है, जहां शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूदुर राशिद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और डॉ. यास्मीन राशिद सहित कई वरिष्ठ PTI नेता वर्तमान में कैद हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोट लखपत के इन कैदियों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से बातचीत का समर्थन किया है और इसे आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य तरीका बताया है। हालांकि, इमरान खान ने पहले उनकी सलाह को खारिज

कर दिया था और सार्वजनिक रूप से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया था। उन्होंने जोर दिया था कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प है।

पीटीआई नेताओं की रिहाई की कोशिश सूत्रों ने कहा कि तिकड़ी की रणनीति कोट लखपत के कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ करना है, जिससे एक ऐसे PTI नेतृत्व का उदय हो सके जो, उनके विचार में, जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझता है और अधिक उदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने को तैयार है। संपर्क करने पर, चौधरी ने द न्यूज को पुष्टि की कि राष्ट्रीय संवाद समिति का गठन वास्तव में राजनीतिक माहौल को सामान्य बनाने और PTI और सेना के बीच लंबे समय से चल रहे टकराव को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया है।



ढाका: भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया। भारत की यह तलबी ढाका में भारतीय उच्चायोग को मिल रही धमकियां और बांग्लादेशी नेताओं के भारत विरोधी बयानबाजी के बाद की है।

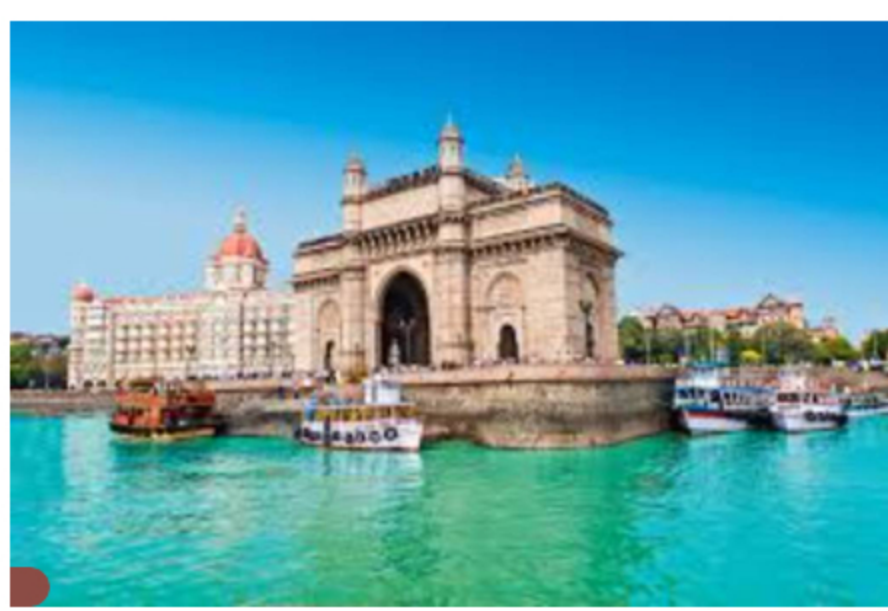
India Bangladesh News: पूर्वोत्तर पर गंदी नजर और भारतीय उच्चायोग पर हमले का खतरा, भारत से उलझ क्यों रहा बांग्लादेश, यूनुस की प्लानिंग समझिए

इस दौरान भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त के सामने औपचारिक रूप से राजनयिक विरोध दर्ज कराया। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्ला को ढाका में भारतीय उच्चायोग को मिली धमकी पर अपनी चिंता जताई, हालांकि इस दौरान धमकी की सही प्रकृति के बारे में नहीं बताया। भारत ने 2024 में हसीना विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी ढाका के उच्चायोग से गैर ज़रूरी कर्मचारियों और उनके आश्रितों की निकाल लिया था।

विदेश मंत्रालय ने जारी किया कड़ा बयान विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया,"भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त, महामहिम श्री रियाज हमीदुल्ला को आज (17 दिसंबर, 2025) विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया और बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंताओं से अवगत कराया गया। उनका ध्यान विशेष रूप से कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर दिलाया गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सुरक्षा की स्थिति पैदा करने की योजना की घोषणा की है।" इसमें आगे कहा गया, "भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के बारे में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए जा रहे झूठे नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो पूरी जांच की है और न ही इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किया है।"

बांग्लादेश के साथ संबंधों का जिक्र भारत ने आगे कहा, "भारत के बांग्लादेश के लोगों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में हैं, और जो विभिन्न विकासात्मक और लोगों से लोगों के बीच की पहलों से मजबूत हुए हैं। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं और हमने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों का आह्वान किया है। हम अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह अपने राजनयिक दायित्वों के अनुसार बांग्लादेश में मिशनों और चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।"

भारत विरोधी ताकतें चाहती क्या हैं बांग्लादेश में वर्तमान में सत्ता पर काबिज मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से एंटी-इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हुए हैं और भारत के साथ तल्लेखियां बढ़ी हैं। यूनुस चाहते हैं कि भारत शेख हसीना को किसी भी तरह उन्हें सौंप दे ताकि बांग्लादेश में उन्हें फांसी पर लटकाया जा सके। बांग्लादेश में 12 फरवरी में चुनाव होने हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और छात्र आंदोलन के नेता समेत सभी भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। वे बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनावर बांग्लादेशी लोगों का ध्यान अंदरूनी मुद्दों से भटकना चाहती हैं, ताकि वोट हासिल किए जा सकें। हालांकि, इन सभी की सत्ता पाने की लालच ने पिछले डेढ़ साल से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क किया हुआ है।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Thursday 18th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 232 , पृष्ठ 03



लोकसभा में मनरेगा नाम परिवर्तन पर ओवैसी का तीखा विरोध, विपक्ष ने बुलंद आवाज़ उठाई

नई दिल्ली — लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” (VB-G RAM G) बिल पेश किए जाने के बाद विरोधी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह नया विधेयक सदन में पेश किया, जिसका उद्देश्य पुराने मनरेगा को निरस्त कर 125 दिनों की रोजगार गारंटी के साथ नया ढांचा तैयार करना है।

इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित कई विपक्षी सांसदों ने सरकार पर हमला बोला और इस नाम परिवर्तन को मनरेगा की मूल भावना व गांधीजी की विरासत के प्रति अनादर करार

दिया। विपक्ष का कहना है कि मनरेगा जैसे योजना का नाम बदलना और महात्मा गांधी का नाम हटाना सामाजिक-राजनीतिक विवाद उत्पन्न कर रहा है और इससे ग्रामीण रोजगार की साख पर प्रश्नचिन्ह उठता है।

ओवैसी के विरोध ने उस व्यापक नाराज़गी का प्रतिनिधित्व किया जो विपक्षी दलों में दिख रही है। कांग्रेस समेत कई दलों ने भी इस कदम को गांधीजी के आदर्शों के प्रति अनुरूप न होने वाला कदम बताया और सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की है। राजनीतिक गलियारे से लेकर विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं तक, मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विशाल प्रतिक्रिया और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिससे यह विषय संसद से बाहर भी गहरे बहस का विषय बन गया है।

अंबरनाथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदाता सभा में मेट्रो योजना तथा पारदर्शी संचालन पर जोर दिया

कल्याण | अंबरनाथ (कल्याण-डोंबिवली) — महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 दिसंबर 2025 को अंबरनाथ में नगर परिषद चुनाव प्रचार सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विकास योजनाओं और पारदर्शी शासन-व्यवस्था पर विस्तार से बात की। सभा का आयोजन 20 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद चुनावों से ठीक पहले किया गया था, जिसमें भाजपा की जीत और विकास पर जोर देने के लिए फडणवीस ने जनता से समर्थन मांगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबरनाथ और बदलापुर के लिए मेट्रो-14 सेवा बेहद महत्वपूर्ण होगी और इसके लिए सरकार अगले चार महीनों में काम शुरू करेगी। यह मेट्रो लाइन बदलापुर से कंजूरमार्ग तक विस्तार करेगी और इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि 370 किमी मेट्रो नेटवर्क योजना तैयार है और मेट्रो-5, 12 और 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे अंबरनाथ को विशेष लाभ मिलेगा।



फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल आलोचना नहीं, बल्कि विकास एजेंडा देना है। उन्होंने कहा कि जिनके पास विकास की योजना नहीं होती, वे आलोचना करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार शहर में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन लाना चाहती है। उन्होंने इसीलिए ‘CA नगराध्यक्ष’ यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में नगराध्यक्ष चुनने का सुझाव दिया, जो सभी वित्तीय रिकॉर्ड का

हिसाब रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर ठीक-ठीक हिसाब करेंगे।

रेल सुधारों पर भी फडणवीस ने कहा कि कल्याण-बदलापुर रेलवे मार्ग पर काम तेजी से चल रहा है, और उन्होंने रेल मंत्रालय से 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन को अंबरनाथ तक बढ़ाने की मांग की। फडणवीस ने कहा कि भविष्य में इन ट्रेनों को एयर-कंडीशनड बनाया जाएगा, और टिकट किराया नहीं बढ़ाया जाएगा।

शहर की बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी और कचरा प्रबंधन की चुनौतियों का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शीलार और पोशीर धरणों का निर्माण शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय में पानी की समस्या को काफी हद तक हल करेगा।

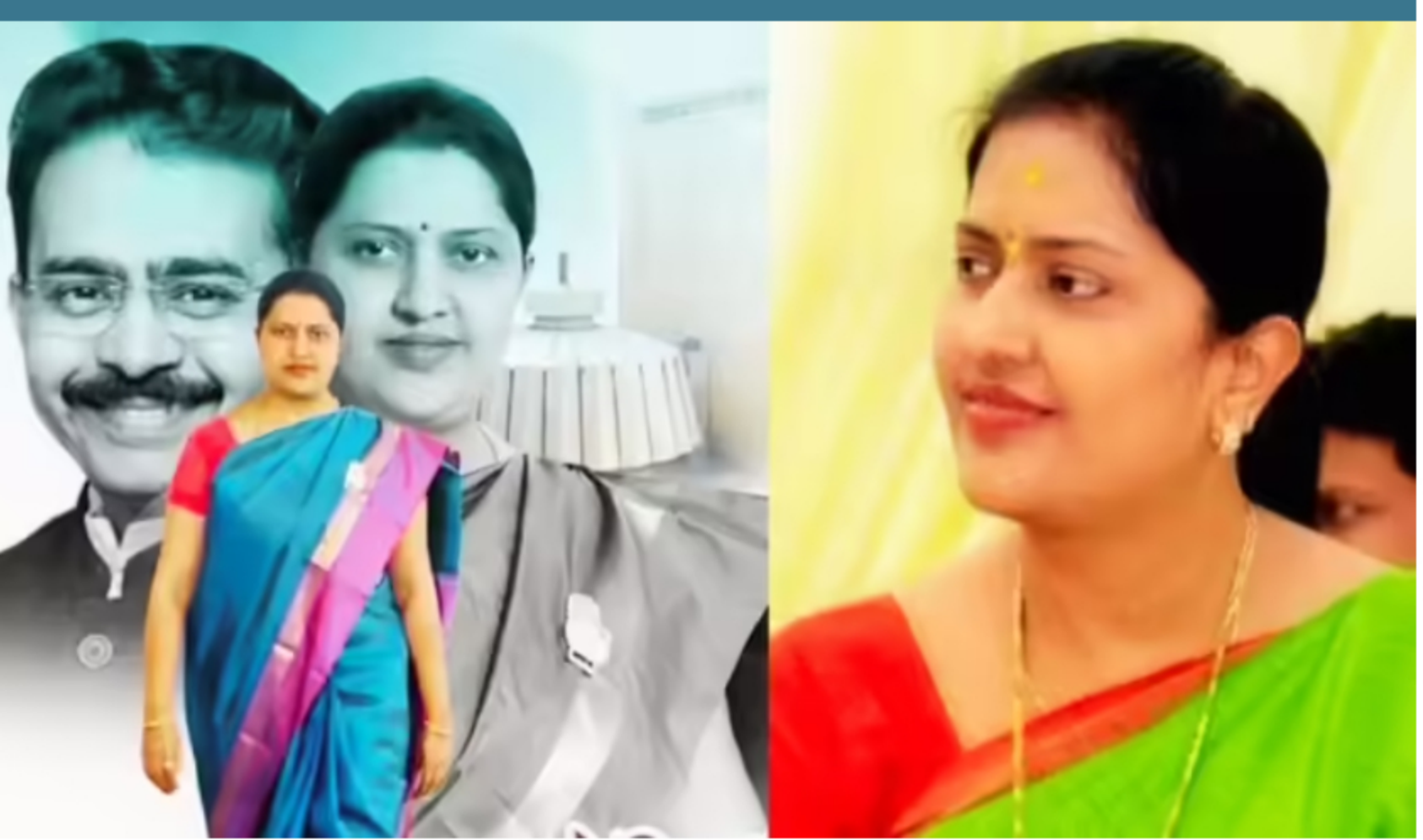
इस बीच अंबरनाथ में भाजप उम्मीदवार के कार्यालय पर गोलीबार जैसी घटनाओं की खबरें भी सामने आईं, जिससे चुनावी माहौल में तनाव का संकेत मिला। फडणवीस ने जनता से आह्वान किया कि विकास-केंद्रित नेतृत्व को चुना जाए ताकि शहर की समस्याओं का समाधान जल्दी हो और अंबरनाथ-बदलापुर क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

Maharashtra Politics: विधायक प्रज्ञा सातव BJP में होंगी शामिल! निकाय चुनावों के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका

मुंबई। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद लगातार झटके लगते रहे हैं। कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से पहले ही कमजोर हो चुकी कांग्रेस के लिए अब एक और चिंता की खबर सामने आई है। गांधी परिवार के वफादार और राहुल गांधी के करीबी रहे दिवंगत सांसद डॉ. राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। इस खबर से महाराष्ट्र कांग्रेस में हड़कंप मच गया है।

प्रज्ञा सातव वर्तमान में महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य हैं। कांग्रेस ने उन्हें वर्ष 2021 में विधान परिषद भेजा था। 17 मार्च 1976 को जन्मी प्रज्ञा सातव पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। वे कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और विधान परिषद में पार्टी की इकलौती महिला सदस्य हैं। उनके पति डॉ. राजीव सातव का निधन 16 मई 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण हुआ था।

राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव के बीजेपी में जाने की अटकलें

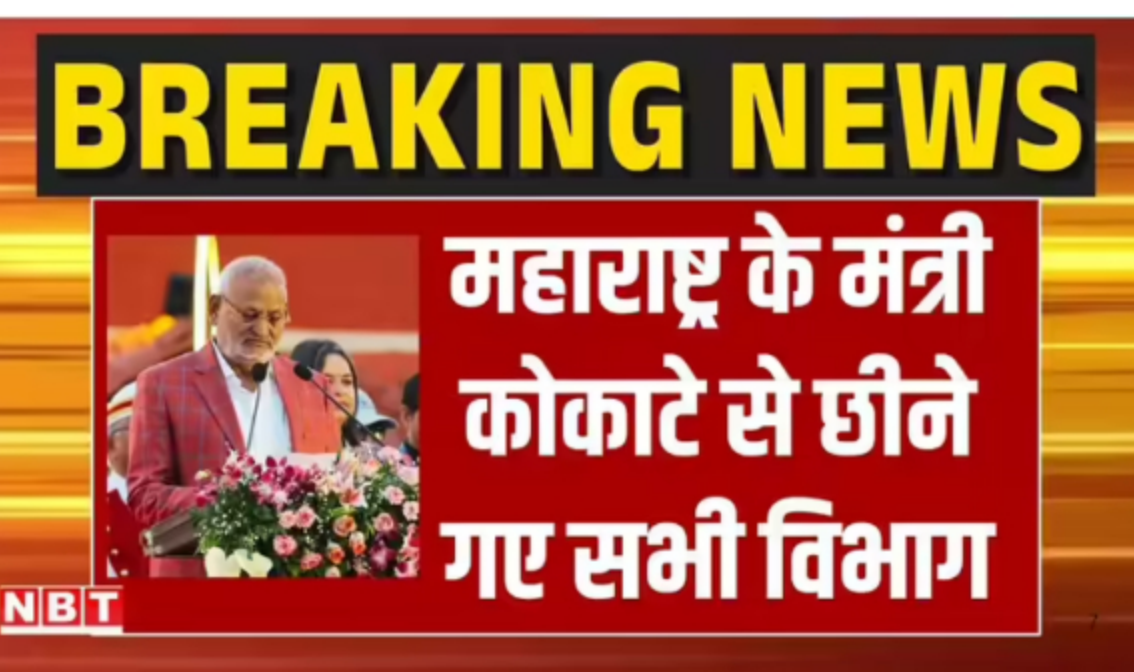


सूत्रों के अनुसार, प्रज्ञा सातव के साथ दो अन्य विधायक भी पाला बदल सकते हैं। बीते दो वर्षों में कांग्रेस को अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी जैसे नेताओं के जाने से बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी

का हिस्सा है और लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनावों में वह शिवसेना (यूबीटी) से पीछे रह गई थी। आगामी बीएमसी और नगर निगम चुनावों से पहले यह घटनाक्रम कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

मंत्री कोकाटे से छीने गए विभाग, अजित पवार को मिला चार्ज, राज्यपाल ने जारी किया पत्र, महाराष्ट्र में बड़ी हलचल

मुंबई | नासिक कोर्ट द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने और फिर अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे से तमाम विभाग ले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने माणिकराव कोकाटे के तमाम विभागों को उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सौंप दिया है। माणिकराव कोकाटे फडणवीस सरकार में खेल-कूद व युवा कल्याण मंत्री थे। सूत्रों की मानें तो नासिक कोर्ट के फैसले के बाद ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से बात की थी। इसके बाद के घटनाक्रम में यह सब हुआ, हालांकि अभी तक कोकाटे का इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन उनका इस्तीफा भी हो सकता है। दरअसल, कोर्ट से सजा सुनाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र



फडणवीस ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से अनुरोध किया था कि कोकाटे का मंत्री पद उपमुख्यमंत्री अजित पवार को सौंप दी जाए। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करते हुए देर रात पत्र जारी किया। हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया मना फिलहाल माणिकराव कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन विभाग वापस लिए जाने के कारण वे

वर्तमान में बिना विभाग के मंत्री हैं। क्रीड़ा मंत्री माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने तात्कालिक सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं, कोकाटे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लगभग तय मानते हुए विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की मांग की थी।

कोकाटे अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर और सीनियर नेता है। अजित पवार की पार्टी के सामने यह नई मुश्किल ऐसे वक्त पर आई है। जब छगन भुजबल पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि इस सब घटनाक्रम के उधर दिल्ली में पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंत्री कोकाटे पहले कृषि मंत्री थे। रमी विवाद के बाद उनके विभाग बदले गए थे।

मुंबई-गोवा महामार्ग पर भीषण हादसा, कार चालक की मौके पर मौत



रत्नागिरी। मुंबई-गोवा महामार्ग पर एक बार फिर दर्दनाक हादसा हुआ है। रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तालुका अंतर्गत तुरळ गांव के पास बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार सड़क किनारे लगे लोहे के गार्डर से टकरा गई। हादसे में कार चालक सलीम सुल्तान खान (46), निवासी वसई की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गार्डर कार के भीतर घुस गया और चालक को गंभीर चोट लगी, जिससे वह वाहन से बाहर जा गिरा। कार में मौजूद उनका मित्र सुखविंदर संधू (46), निवासी मीरा रोड, मामूली रूप से घायल हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक और संगमेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को उपचार के लिए संगमेश्वर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।



मुंबई। मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ महायुति ने जहां सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है, वहीं विपक्षी खेमे में भी नई राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। यह लगभग तय माना जा रहा है कि मुंबई में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर

मुंबई महापालिका चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, शरद पवार ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे के बीच भी गठबंधन की प्रबल संभावना जताई जा रही है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है।

इस बीच कांग्रेस ने मुंबई महापालिका चुनाव स्वबल पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) एक आश्चर्यजनक निर्णय की ओर बढ़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस को दरकिनार कर शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के साथ गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

मुंबई में शरद पवार गुट की ताकत सीमित मानी जाती है, हालांकि कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी का प्रभाव है। पार्टी के पास फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद एनसीपी (शप) ठाकरे बंधुओं के साथ जाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी 227 वार्डों वाली मुंबई महानगरपालिका में 20 से 25 सीटों की मांग कर रही है। मालवणी, मालाड, थारावी, बांद्रा और कुर्ला जैसे इलाकों पर उसकी

नजर है।

इस संबंध में शुक्रवार को मुंबई में एनसीपी (शप), शिवसेना (यूबीटी) और मनसे की एक अहम बैठक प्रस्तावित है। यह तीनों दलों की पहली संयुक्त बैठक होगी, जिसमें गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। वहीं एनसीपी (शप) के प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि पार्टी की इच्छा है कि महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़े। उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं और 21 तारीख की बैठक में कांग्रेस को भी आमंत्रित किया जाएगा।

गौरतलब है कि 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, भाजपा को 82, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 और मनसे को 7 सीटें मिली थीं। उसके बाद शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन से राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। ऐसे में आगामी चुनाव मुंबई की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।



नांदेड़ वॉक्स

नांदेड़ जिला > नांदेड़ शहर



नांदेड़ग्राम टाइम्स

संवाददाता चाहिए

नांदेड़ग्राम टाइम्स,
दैनिक समाचार पत्र, नांदेड़
को
महाराष्ट्र और नांदेड़ जिले के
प्रत्येक तालुका और शहर से
संवाददाता की आवश्यकता
है।

यदि आप समर्पित, उत्साही
और अवसर की तलाश में
उभरते या अनुभवी पत्रकार
हैं, तो हमसे तुरंत व्हाट्सएप
पर संपर्क करें।

आपकी कलम ही हमारी
ताकत है!

संपर्क करें
+919921100075
+919921100075

NANDED NEWS | नांदेड़ महापालिका चुनाव 2025

नांदेड़ महापालिका चुनाव 2025 : 1.20 लाख नए मतदाता बनेंगे निर्णायक, 5.17 लाख तय करेंगे शहर की सत्ता

नांदेड़ : नांदेड़-वाघाला शहर
महानगरपालिका के सार्वजनिक
चुनाव का ऐलान होते ही
राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो
गई हैं। लगभग साढ़े आठ वर्ष
बाद शहर के नागरिकों को फिर
से मतदान का अवसर मिलने जा
रहा है। पिछला चुनाव 11
अक्टूबर 2017 को हुआ था।
इस बार 15 जनवरी को 20
प्रभागों में मतदान और 16
जनवरी को मतगणना होगी।



इन सुधारों के बाद 20 दिसंबर
को अंतिम मतदाता सूची
प्रकाशित की जाएगी। इसके
बावजूद लगभग 1.18 लाख
अतिरिक्त मतदाता इस चुनाव
में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

नांदेड़ महापालिका 'ड' श्रेणी में
आती है, इसलिए प्रत्येक
उम्मीदवार के लिए 9 लाख रुपये
की खर्च सीमा तय की गई है।
बहुसदस्यीय प्रणाली के तहत
20 प्रभागों से 81 नगरसेवक
चुने जाएंगे। इस चुनाव में
वीवीपेट का उपयोग नहीं होने से
भी चर्चाएं तेज हैं।

पिछले चुनाव में करीब 60
प्रतिशत मतदान हुआ था,
जबकि हालिया नगरपालिका
चुनावों में 81 प्रतिशत से अधिक
मतदान दर्ज किया गया। ऐसे में
इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना
प्रशासन और राजनीतिक दलों
के सामने बड़ी चुनौती है।

जिनमें 2 लाख 71 हजार 69
पुरुष, 2 लाख 46 हजार 666
महिलाएं और 104 तृतीयपंथी
मतदाता शामिल हैं। महिला
मतदाताओं की संख्या अधिक
होने से उनके रुझान को चुनावी
परिणाम की चाबी माना जा रहा
है।

चुनाव प्रक्रिया के अनुसार 23 से
30 दिसंबर तक नामांकन पत्र
दाखिल किए जाएंगे। 31 दिसंबर

को नामांकन की जांच होगी, 2
जनवरी नाम वापसी की अंतिम
तिथि रहेगी और 3 जनवरी को
चुनाव चिन्हों के साथ अंतिम
उम्मीदवार सूची जारी की
जाएगी। इसके बाद प्रचार की
रणधुमाल शुरू होगी।
महापालिका की प्रारूप मतदाता
सूची पर 348 आपत्तियां प्राप्त
हुई हैं और करीब 7,500
मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टि
सामने आई है।



श्रीक्षेत्र मालेगांव यात्रा का आज से शुभारंभ, श्री खंडोबा की पालकी का होगा पूजन

नांदेड़ (संवाददाता) : दक्षिण भारत में प्रसिद्ध
लोहा तालुका स्थित श्रीक्षेत्र मालेगांव में श्री
खंडोबा की वार्षिक यात्रा का शुभारंभ आज,
गुरुवार 18 दिसंबर से हो रहा है। इस अवसर पर
दोपहर 1 बजे देवस्वारी निकाली जाएगी तथा श्री
खंडोबा की पालकी का विधिवत पूजन संपन्न
होगा। कार्यक्रम में जिला परिषद की मुख्य
कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, लोहा-कंधार
के विधायक प्रतापराव पाटील चिखलीकर सहित
अनेक मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति रहेगी।

लाखों श्रद्धालु मालेगांव यात्रा में शामिल होने की
संभावना है।

यात्रा के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए
जिला परिषद प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु चलित शौचालय,
स्वास्थ्य सेवाएं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, तथा
निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रा परिसर में सीसीटीवी
कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, पशुसंवर्धन विभाग की
ओर से पशुओं के लिए विशेष पशु चिकित्सालय
भी शुरू किए गए हैं।

श्रद्धा, परंपरा और लोकसंस्कृति का संगम मानी
जाने वाली श्रीक्षेत्र मालेगांव की यह यात्रा एक
बार फिर भक्ति और उत्सव का वातावरण
बनाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए
रखने और यात्रा का आनंद अनुशासन के साथ
लेने की अपील की है।

गोकुंदा उपजिला अस्पताल 'रेफर' बीमारी का शिकार, अव्यवस्थाओं से मरीज बेहाल

किनवट | संवाददाता
आदिवासी बहुल किनवट तालुका
के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोकुंदा
उपजिला अस्पताल आज मूलभूत
स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से
जूझ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की
कमी के चलते यह अस्पताल मानो
'रेफर करने की बीमारी' से ग्रस्त हो
गया है। गंभीर मरीजों को मजबूरी
में आदिवासी मरीजों पर आर्थिक व
मानसिक बोझ बढ़ गया है।



यहां कुल 13 चिकित्सा अधिकारियों के पद
स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 10 डॉक्टर
ही कार्यरत हैं। तीन डॉक्टरों व तीन कक्षसेवकों
की प्रतिनियुक्ति से मरीज सेवाएं प्रभावित हुई
हैं। नेत्र जांच व आंखों की शल्यक्रिया सुविधा
के अभाव में बुजुर्ग मरीजों को बाहर भटकना
पड़ रहा है। रक्तपेढ़ी होते हुए भी पर्याप्त
रक्तसंग्रह नहीं है।

औषधि निर्माण अधिकारियों के रिक्त पदों से
दवा वितरण व्यवस्था भी चरमराई हुई है। वर्षों
से निष्क्रिय रुग्णकल्याण समिति को लेकर
नागरिकों में नाराजगी है। नांदेड़ से 150 किमी
दूर स्थित इस अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग
द्वारा तत्काल ध्यान देने की मांग जोर पकड़ रही
है।

नांदेड़ में कानून-व्यवस्था सख्त, एसडीएम ने एक वर्ष में 23 अपराधियों को किया तड़ीपार

नांदेड़ | संवाददाता :

शहर में कानून और व्यवस्था
बनाए रखने के उद्देश्य से
जिला कलेक्टर राहुल कर्डिले
के मार्गदर्शन में नांदेड़ के
उपविभागीय दंडाधिकारी
(एसडीएम) डॉ. सचिन
खल्लाळ ने वर्ष 2025 के
दौरान कड़ा कदम उठाते हुए
गंभीर अपराधों में संलिप्त 23
अपराधियों को तड़ीपार करने
की कार्रवाई की है। यह
कार्रवाई जिले के विभिन्न
पुलिस थाना क्षेत्रों में की गई
है।



तड़ीपार किए गए अपराधियों
के खिलाफ शस्त्र अधिनियम,
पॉक्सो अधिनियम सहित
अन्य गंभीर प्रकृति के
अपराध दर्ज हैं।

इन अपराधियों की आयु
23 से 35 वर्ष के बीच
बताई जा रही है। थाना
क्षेत्रवार आंकड़ों के
अनुसार नांदेड़ ग्रामीण क्षेत्र
से 13, इतवारा से 6,
विमानतल से 2,
वजिराबाद से 1 तथा
शिवाजीनगर थाना क्षेत्र से
1 अपराधी को तड़ीपार
किया गया है। प्रशासन का

कहना है कि यह कार्रवाई
शहर में बढ़ती आपराधिक
गतिविधियों पर अंकुश
लगाने और आम नागरिकों
में सुरक्षा की भावना
मजबूत करने के उद्देश्य से
की गई है। तड़ीपार किए
गए अपराधियों की
गतिविधियों से शांति भंग
होने की आशंका को देखते
हुए यह निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर उपविभागीय
दंडाधिकारी डॉ. सचिन
खल्लाळ ने नागरिकों से
अपील की कि वे कानून-
व्यवस्था बनाए रखने में
प्रशासन का सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी
आपराधिक प्रवृत्ति, संदिग्ध
गतिविधि या कानून का
उल्लंघन होता दिखाई दे, तो
तुरंत पुलिस या प्रशासन को
सूचित करें। सुरक्षित, शांत
और भयमुक्त नांदेड़ के
निर्माण में नागरिकों की
सक्रिय भागीदारी आवश्यक
है।

प्रशासन की इस सख्त
कार्रवाई से शहर में अपराध
पर नियंत्रण और कानून-
व्यवस्था को मजबूती मिलने
की उम्मीद व्यक्त की जा रही
है।

चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर सख्ती, नाबालिग के मामले में माता-पिता पर होगा मामला

नांदेड़। संक्रांति पर्व नजदीक आते ही शहर में
पतंगबाजी का उत्साह बढ़ गया है, लेकिन इसके
साथ ही जानलेवा चाइनीज और नायलॉन मांझे
का खतरा भी सामने आ रहा है। इसी को देखते
हुए नांदेड़ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट
चेतावनी जारी की है कि प्रतिबंधित मांझे का
इस्तेमाल किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया
जाएगा।

पुलिस विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि कोई
नाबालिग बच्चा चाइनीज या नायलॉन मांझे का
उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसके माता-
पिता के खिलाफ सीधे सदीय मनुष्यवध का
मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे
मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर भी
तत्काल आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह
निर्णय लिया गया है।

मांझे से हादसा या मौत होने पर गंभीर अपराध
यदि चाइनीज या नायलॉन मांझे के कारण किसी
व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है या मृत्यु होती है,
तो इसे गंभीर और गैर-जमानती अपराध माना
जाएगा। ऐसी स्थिति में मांझा इस्तेमाल करने

वाले व्यक्ति के माता-पिता अथवा मांझा बेचने
वाले दुकानदार पर सदीय मनुष्यवध का मामला
दर्ज किया जाएगा।

महानगरपालिका की छापेमारी
महानगरपालिका प्रशासन भी पुलिस के साथ
मिलकर शहरभर में दुकानों की जांच और
छापेमारी करेगा। प्रतिबंधित मांझा बेचने या
छिपाकर रखते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की
जाएगी।

प्रतिबंधित मांझे पर पूर्ण रोक
नायलॉन, चाइनीज तथा कांच की परत वाले
सभी प्रकार के मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यह
मांझा पर्यावरण और मानव जीवन दोनों के लिए
अत्यंत घातक है। इसके उपयोग या बिक्री पर दंड
और कारावास का प्रावधान है।

नागरिकों से अपील
यदि कहीं भी चाइनीज या नायलॉन मांझे की
बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो नागरिक
तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से सुरक्षित और
पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने की
अपील की है।

हिमायतनगर में शिक्षा संकट गहराया: 21 स्कूलों में 20 से कम छात्र, 10 स्कूल एक-शिक्षक के भरोसे



हिमायतनगर (नांदेड़)। तालुका हिमायतनगर में
प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक
होती जा रही है। शिक्षा विभाग से प्राप्त
जानकारी के अनुसार, तालुके में जिला परिषद
की 21 प्राथमिक शालाओं में छात्रों की संख्या
20 से भी कम है। इससे भी अधिक गंभीर
स्थिति यह है कि 10 स्कूल केवल एक शिक्षक के
भरोसे संचालित हो रहे हैं।

ऐसे में पालकों के सामने बड़ा सवाल खड़ा
हो गया है कि उनके बच्चे कहां और कैसे
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें?

महादापुर और चिंचोर्डा जैसे आदिवासी
बहुल गांवों में क्रमशः 60 और 65 छात्रों
की उपस्थिति होने के बावजूद इन स्कूलों में
सिर्फ एक-एक शिक्षक कार्यरत है। स्थानीय
नागरिकों का आरोप है कि शिक्षकों की
कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई पर
सीधा असर पड़ रहा है। महिला शक्ति
कार्यकर्ता महानंदा ढोले, सरपंच गंगाराम
ढोले, शंकर वाघतकर, संदीप झळके और
बंडू बुरकुले ने इन दोनों गांवों में रिक्त
शिक्षक पदों को तत्काल भरने की मांग
शिक्षा विभाग से की है।

पालकों का कहना है कि 20 से कम छात्र
संख्या वाली 21 शालाओं के कारण वाड़ी-
तांडा क्षेत्रों की स्कूलें बंद होने के खतरे में
हैं। शासन स्तर पर ऐसी शालाओं को बंद

करने की नीति पर विचार किए जाने से
ग्रामीणों में असंतोष है। उनका मानना है
कि इन स्कूलों को बचाने के लिए स्थानीय
स्तर पर ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

इस समस्या के पीछे अंग्रेजी माध्यम के
स्कूलों की ओर बढ़ता रुझान और मराठी
माध्यम की शालाओं में घटती छात्र संख्या
को मुख्य कारण बताया जा रहा है। पालकों
का कहना है कि यदि बच्चों को कम से कम
चौथी-पांचवीं तक मातृभाषा (मराठी) में
शिक्षा दी जाए, तो उनकी शैक्षणिक नींव
अधिक मजबूत होगी।

तालुके की 10 एक-शिक्षक शालाओं में
स्थिति और भी गंभीर है। यदि शिक्षक को
बैठक, प्रशिक्षण या अवकाश के लिए बाहर
जाना पड़े, तो स्कूल पूरी तरह बंद हो जाता
है। इसलिए पालकों ने हर एक-शिक्षक
स्कूल में कम से कम दो शिक्षक नियुक्त
करने की मांग की है।

इस संबंध में गट शिक्षणाधिकारी केशव
मेकाले ने बताया कि तालुके में 52 शिक्षक
पद रिक्त हैं। इसके अलावा केंद्र प्रमुख के
6 पद और विस्तार अधिकारियों के 3 पद
भी खाली हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर
15 शिक्षक न्यायालय गए हैं, जिससे
अस्थायी रूप से एक-एक शिक्षक की
व्यवस्था की गई है। सभी पद भरने और
न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद
शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। फिलहाल
उपलब्ध संसाधनों में समायोजन कर
शैक्षणिक व्यवस्था चलाई जा रही है।

तालुके में शिक्षा का यह चित्र प्रशासन के
लिए चेतावनी है कि यदि समय रहते ठोस
निर्णय नहीं लिए गए, तो ग्रामीण और
आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का भविष्य खतरे
में पड़ सकता है।

